ईरान युद्ध से अमेरिकी खजाना खाली

- जंग में अब तक 36.10 खरब फूंके
- हर महीने 2.85 खरब का खर्च
- महंगाई बढ़ने की सीबीओ ने चेतावनी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 सितंबर मिडिल ईस्ट के रण में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब अमेरिकी खजाने पर भारी पड़ने लगी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जंग की जिद अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है.

कांग्रेसनल बजट ऑफिस की ताजा रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस जंग में केवल बारूद नहीं जल रहा बल्कि अमेरिकी करदाताओं की गाढ़ी कमाई के खरबों रुपये धू-धू कर स्वाहा हो रहे हैं. 1 अगस्त तक ही इस जंग पर अमेरिका 36.10 खरब रुपये से अधिक फूंक चुका है. हैरानी की बात यह रही कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने सामान्य नियमों के उलट सीबीओ को युद्ध खर्च से जुड़े आंकड़े देने से साफ इनकार कर दिया. इसके बावजूद बजट कार्यालय ने स्वतंत्र सरकारी डेटाबेस और सार्वजनिक दस्तावेजों को खंगालकर यह कच्चा-चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया. इस साल 28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका ईरान युद्ध अब अपने सातवें महीने में प्रवेश कर चुका है. इसके जल्द थमने का कोई संकेत भी नजर नहीं आ रहा है. सीबीओ के आकलन के मुताबिक, जंग की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग को आगे भी हर महीने कम से कम 2.85 खरब रुपये या उससे अधिक की भारी रकम खर्च करनी पड़ेगी. यह अनुमान रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के उस बयान से भी मेल खाता है जिसमें उन्होंने सीनेट के सामने युद्ध की लागत करीब 35.62 खरब रुपये बताई थी.

डिमांड पर नहीं लगाई है मुहर

व्हाइट हाउस ने जून में अतिरिक्त फंडिंग के तौर पर 83.22 खरब की भारी मांग रखी थी जिसमें से लगभग 40.18 खरब सीधे युद्ध के अभियानों के लिए है. हालांकि अमेरिकी संसद ने अब तक इस मांग पर मुहर नहीं लगाई है. इस मुद्दे पर हाउस बजट समिति के शीर्ष डेमोक्रेट सांसद ब्रेडन बॉयल ने ट्रंप प्रशासन और रिपब्लिकन नेताओं पर तीखा हमला बोला है.

चंद्रशेखरन ने फिर संभाली टाटा सन्स की कमान

- फरवरी 2027 में खत्म होगा मौजूदा कार्यकाल
- टाटा संस की सूचीबद्धता पर भी चर्चा

नवभारत न्यूज नेटवर्क

मुंबई, 17 सितंबर. टाटा समूह की शीर्ष होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड ने एन. चंद्रशेखरन को कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर पांच साल का नया कार्यकाल देने की मंजूरी दे दी है.

उनका मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त होना है. इससे पहले अगस्त में चंद्रशेखरन ने मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद नए कार्यकाल की मांग नहीं करने का फैसला लिया था. अब बोर्ड के फैसले के बाद टाटा संस के नेतृत्व को लेकर स्थिति बदल गई है.

पांच साल के नए कार्यकाल को मंजूरी

चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति की खबरों के बीच टाटा समूह की कई सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में कारोबार के दौरान तेजी देखने को मिली. टाटा पावर के शेयर करीब दो फीसदी चढ़कर 370 रुपए के स्तर तक पहुंचे.

टाटा स्टील में करीब तीन फीसदी की तेजी रही और शेयर 190 रुपए के आसपास पहुंच गया. टाटा केमिकल्स में करीब छह फीसदी का उछाल आया और भाव 775 रुपए के पार पहुंच गया.

चावल पर महंगाई की मार

- नॉन-बासमती चावल में 20 से 25 फीसदी उछाल
- कम बारिश और निर्यात मांग से सप्लाई पर असर

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 सितंबर रसोई के बजट पर एक बार फिर दबाव बढ़ गया है. बासमती से लेकर आम नॉन बासमती चावल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में - बासमती चावल के दाम पिछले साल के मुकाबले 15 से 20 - फीसदी तक बढ़ चुके हैं, जबकि रोजमर्रा की नॉन-बासमती किस्मों की कीमतों में 20 से 25 फीसदी का उछाल आया है. व्यापारियों और निर्यातकों का कहना है कि जब तक अक्टूबर-नवंबर में नई फसल बाजार में नहीं आ जाती तब तक कीमतें ऊंची बनी रहने की संभावना है. कीमतों में इस उछाल के पीछे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह के कारण जिम्मेदार हैं.

ग्लोबल डिमांड और तनाव: यूएस-ईरान युद्ध के चलते कई देश अपना फूड सप्लाई सुरक्षित करने के लिए तेजी से चावल खरीद रहे है. खासतौर पर गल्फ देशों से भारतीय चावल की भारी मांग आ रही है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में कम बारिश के कारण पैदावार और सप्लाई प्रभावित हुई है. राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक, सार्वजनिक वितरण के लिए तेलंगाना द्वारा की जा रही गैर-बासमती चावल की खरीद से भी सप्लाई टाइट हुई है

इसके अलावा, अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने और गल्फ देशों की तरफ से खरीदारी की रफ्तार धीमी होने पर ही बाजार में स्थिरता आ पाएगी. तब तक आम उपभोक्ताओं को महंगे चावल के साथ ही तालमेल बिठाना होगा.

नवंबर तक कीमतें ऊंची रहने की उम्मीद

केआरबीएल लिमिटेड के बल्क राइस एक्सपोर्ट्स हेड अक्षय गुप्ता के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 154 देशों को रिकॉर्ड 65.2 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया जिसमें सऊदी अरब सबसे बड़ा खरीदार रहा. गल्फ कॉरिडोर में पेमेंट और शिपिंग की रुकावटों के कारण सप्लाई - थोड़ी धीमी हुई है लेकिन मांग मजबूत बनी हुई है. हालांकि गुप्ता का कहना है कि वर्ष 2025 की फसल - तेजी से बिक गई और अक्टूबर की नई आवक से पहले बहुत कम स्टॉक बचा है. यानी घरेलू कीमतों में तेजी का मुख्य कारण बाजार में स्टॉक की कमी है, न कि केवल निर्यात. फिलहाल जल्द राहत मिलने के आसार कम ही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि नई खरीफ फसल आने (अक्टूबर-नवंबर) तक कीमतें ऊंची रहेंगी.

तनिष्क ने बाजार में बढ़ाया डायमंड खरीद का भरोसा

- देशभर में 225 से ज्यादा स्टोर तक पहुंचा डीएक्ससी
- ग्राहक खुद जांच सकेंगे हीरे की गुणवत्ता

नवभारत कनेक्ट

भोपाल, 17 सितंबर आजकल भरोसे को सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं लिया जाता. इसे खोजा जाता है, अनुभव किया जाता है, और अक्सर चुपचाप वेरिफ़ाई किया जाता है.

अलग-अलग कैटेगरी में, कस्टमर जो खरीदते हैं, उसके करीब जा रहे हैं, सिर्फ़ जानकारी नहीं चाहते, बल्कि चीज़ों को खुद देखकर मिलने वाला पक्कापन चाहते हैं. लंबे समय तक, डायमंड इस बदलाव से बाहर रहे. खरीदने का सफ़र एक्सपर्टाइज़ से गाइड होता था, सर्टिफिकेशन से सपोर्ट मिलता था, और भरोसे पर बना होता था. भरोसेमंद होने के साथ-साथ, इसने दूरी भी बनाई. एक डायमंड के बारे में डिटेल में बताया जा सकता था, लेकिन शायद ही कभी इस तरह से कि वह तुरंत या सच में ठोस लगे. वह दूरी अब खत्म होने लगी है.

भारत में पहली बार, कोई ज्वेलरी ब्रांड डायमंड इवैल्यूएशन के साइंस को सीधे कस्टमर के सामने, इन-स्टोर एक्सपीरियंस में ला रहा है.

एनएसई ने एंकर निवेशकों से जुटाए 6746.1 करोड़

- 22,569 करोड़ रुपये का है आईपीओ
- 1,785 रुपये तक तय हुआ मूल्य
- 24 सितंबर को सूचीबद्धता संभावित

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली, 17 सितंबर. लंबे इंतजार के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ गुरुवार, 17 सितंबर 2026 से निवेशकों के लिए खुल गया.

करीब 22,569 करोड़ रुपये का यह निर्गम देश के बड़े आईपीओ में शामिल है. निवेशक इसमें 21 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे. ऐसे में आवेदन करने से पहले कीमत, न्यूनतम निवेश, निर्गम का आकार और ग्रे मार्केट के संकेतों समेत कुछ अहम बातों को समझना जरूरी है.

ग्रे मार्केट में 125 रुपये प्रीमियम: 17 सितंबर की सुबह उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एनएसई आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 125 रुपये बताया गया. ऊपरी मूल्य दायरे 1,785 रुपये में इसे जोड़ने पर संभावित सूचीबद्धता कीमत करीब 1,910 रुपये बैठती है. हालांकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम अनौपचारिक संकेत है और वास्तविक सूचीबद्धता कीमत इससे अलग हो सकती है.

एंकर निवेशकों से 6,746 करोड़ जुटाए: एनएसई ने एंकर निवेशकों से करीब 6,746.2 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसमें घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने हिस्सा लिया है. भारतीय जीवन बीमा निगम एंकर निवेश में प्रमुख निवेशकों में शामिल रहा.

कब होगा आवंटन और सूचीबद्धता: आईपीओ में आवेदन की अवधि 17 से 21 सितंबर तक है. शेयरों का आवंटन 22 सितंबर को होने की उम्मीद है. इसके बाद एनएसई के शेयरों की बीएसई पर सूचीबद्धता 24 सितंबर को संभावित है.

22,569 करोड़ रुपये का निर्गम

एनएसई का आईपीओ करीब 22,561.57 करोड़ रुपये का है. यह पूरी तरह बिक्री पेशकश यानी ओएफएस है. इसमें कंपनी नए शेयर जारी नहीं कर रही है, बल्कि मौजूदा शेयरधारक करीब 12.64 करोड़ शेयर बेचेंगे. एनएसई का प्रस्तावित मूल्यांकन करीब 4.42 लाख करोड़ रहने का अनुमान है.

1,700 से 1,785 रुपये कीमत

एनएसई ने आईपीओ के लिए शेयर का मूल्य दायरा 1,700 से 1,785 रुपये तय किया है. एक लॉट में 8 शेयर हैं. ऊपरी मूल्य दायरे पर एक लॉट के लिए खुदरा निवेशक को 14,280 रुपये लगाने होंगे. निवेशक इसी मूल्य दायरे में बोली लगा सकेंगे.

बैंक हड़ताल कवरेज पर एआईबीओसी का आभार

नवभारत कनेक्ट

भोपाल, 17 सितंबर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फ़ेडरेशन (एआईबीओसी) मध्यप्रदेश इकाई ने 11 सितंबर 2026 को भोपाल में आयोजित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के प्रदर्शन, रैली एवं सभा की उत्कृष्ट मीडिया कवरेज के लिए समाचार-पत्रों, न्यूज चैनलों एवं डिजिटल मीडिया संस्थानों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है.

एआईबीओसी मध्यप्रदेश इकाई की ओर से जारी आभार एवं धन्यवाद पत्र में कहा गया कि मीडिया संस्थानों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर कार्यक्रम को गरिमापूर्ण एवं प्रभावी मीडिया कवरेज प्रदान की. संवाददाताओं, फोटोग्राफरों एवं कैमरामैन की सम्मानजनक उपस्थिति ने बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जायज़ मांगों तथा उनके शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक आंदोलन को व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

पत्र में कहा गया कि मीडिया द्वारा पांच दिवसीय बैंक सप्ताह लागू करने, पीएलआई योजना में आवश्यक संशोधन करने तथा बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान सहित अन्य मांगों को प्रमुखता से प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया. निष्पक्ष, सकारात्मक एवं प्रभावी कवरेज से आंदोलन की आवाज आम जनता, प्रशासन और संबंधित पक्षों तक पहुंची. एआईबीओसी ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता प्रदान कर समाज के सामने रखने में मीडिया संस्थानों की भूमिका अत्यंत सराहनीय है.

43वां तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली, 17 सितंबर भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के कमांडरों के सम्मेलन का 43वां संस्करण 17 से 19 सितंबर 2026 तक तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है.

यह शीर्ष वार्षिक सभा विकसित हो रही भू-राजनीतिक गतिशीलता और समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर सार्थक विचार-विमर्श के लिए द्रष्टव्य के वरिष्ठ कमांडरों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है. यह सम्मेलन आईसीजी के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

माननीय रक्षा राज्य मंत्री, संजय सेठ ने आज कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया और महानिदेशक परमेश शिवमणि, एवीएसएम, पीटीएम, टीएम, महानिदेशक आईसीजी और अन्य वरिष्ठ तटरक्षक कमांडरों के साथ राष्ट्रीय और समुद्री सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की. सम्मेलन के दौरान, आईसीजी कमांडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नौसेना प्रमुख के साथ भी बातचीत करेंगे.

पदक से परे संघर्ष को मिला सम्मान

- खिलाड़ियों के सपनों और संघर्षों को मिली पहचान
- परिवार, प्रशिक्षकों के योगदान को सराहा

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली, 17 सितंबर कोई जब पदक जीता जाता है, तो दुनिया केवल जीत का वह क्षण देखती है, लेकिन उस पदक तक पहुँचने का सफर वर्षों लंबा होता है.

इसकी शुरुआत करने के लिए साहस, आगे बढ़ते रहने के लिए दृढ़ता और असफलताओं पर विजय पाने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है. साथ ही, अक्सर परिवार, प्रशिक्षकों और प्रियजनों का वह मौन सहयोग भी इस सफर का अहम् हिस्सा होता है, जो दुनिया के मंच पर खिलाड़ी को देखने से बहुत पहले उसके सपनों के साथ खड़े रहते हैं.

ग्लासगो में पदक जीतने वाले सात पैरा खिलाड़ी सम्मानित

ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सराहनीय प्रदर्शन के पीछे छिपी इन कहानियों को सम्मान देने के उद्देश्य से एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) के साथ मिलकर भारत के उन पैरा खिलाड़ियों को सम्मानित किया.

समाचार विशेष

ओवैसी-बेनीवाल की जोड़ी से भाजपा-कांग्रेस में बेचैनी

गठबंधन का ऐलान कर तीसरा विकल्प खड़ा करने का दावा

नवभारत कनेक्ट

जयपुर, 17 सितंबर. प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनावों के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की जोड़ी ने भाजपा व कांग्रेस के सामने तीसरे विकल्प की सियासी जमीन तैयार करने का दावा किया है.

विगत दिनों जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 146 में एआइएमआइएम की प्रत्याशी फिरोज बानो के समर्थन में आयोजित जनसभा में बेनीवाल और ओवैसी ने गठबंधन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि उनका यह गठबंधन केवल निकाय चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले विधानसभा और अन्य चुनावों में भी मिलकर

बीजेपी व कांग्रेस का मुकाबला करेगा. जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम पक्ष में नहीं आए.

इसके बावजूद उन्होंने राजस्थान में सक्रिय रहने का वादा किया था. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि जब तक लोग अपने वोट से अपनी राजनीतिक लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे, तब तक उनकी आवाज सत्ता के गलियारों में मजबूती से नहीं सुनी जाएगी. ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक हिस्सेदारी के बिना समाज के सपने पूरे नहीं हो सकते हैं.

राजस्थान की राजनीति में एक नई शुरुआत

आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन को राजस्थान की राजनीति में एक नई शुरुआत बताया. उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान, मुस्लिम और अन्य वंचित वर्गों के मुद्दों को मजबूती से उठाने की जरूरत है. उन्होंने ओवैसी की तारीफ करते हुए कहा कि वह कम समय में बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात रखते हैं और संसद में भी संविधान के दायरे में रहकर मजबूती से मुद्दे उठाते हैं. बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में लंबे समय से एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अब जनता के सामने तीसरी ताकत का विकल्प खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जाट और मुस्लिम राजनीतिक रूप से पहले भी साथ रहे हैं और आगे भी साथ रहेंगे.

पंजाब कांग्रेस में झगड़ा सुलझाने का पहला कदम

पंजाब में कांग्रेस में पिछले 25 साल में दो बार सरकार बनी

नवभारत कनेक्ट

चंडीगढ़, 17 सितंबर. पंजाब प्रभारी बनने के साथ ही सचिन पायलट ने कांग्रेस के अंदर का झगड़ा सुलझाने के लिए पहल शुरू कर दी है. उन्होंने दो टूक अंदाज में कह दिया है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ेगी.

असल में इसी बात को लेकर पंजाब कांग्रेस में घमासान छिड़ा है. पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि उनको सीएम का फेस घोषित किया जाएगा. ध्यान रहे वे

पिछले चुनाव के समय पंजाब के सीएम थे और कांग्रेस ने उनको सीएम का चेहरा बना कर चुनाव लड़ा था. वे खुद दो सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों से हार गए थे. कांग्रेस तो बहुत बुरी तरह से हारी. इसलिए कांग्रेस कम से कम उनको तो सीएम चेहरा नहीं ही बना रही थी. लेकिन उनको दिक्कत इस बात से थी कि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग अघोषित रूप से सीएम दावेदार बन गए थे. असल में पंजाब में कांग्रेस में पिछले 25 साल में दो बार सरकार बनी और दोनों बार मुख्यमंत्री वही बना, जो प्रदेश अध्यक्ष था. कैप्टेन अमरिंदर सिंह दोनों बार जब सीएम बने तो वे प्रदेश अध्यक्ष थे. इसलिए चन्नी को लग रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष राजा

चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो उनका अवसर भी बना रहेगा. यह काम सचिन पायलट ने कर दिया है. उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कोई सीएम का दावेदार नहीं होगा. पायलट ने यह भी कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और राहुल गांधी के हाथ में प्रचार की कमान रहेगी. हालांकि दूसरी ओर कम से कम दो बड़ी पार्टियों आप और अकाली दल का चेहरा घोषित है. भगवंत सिंह मान और सुखबीर बादल उधर से नेतृत्व संभालेंगे. उनके अलावा दो अन्य जाट सिख नेता सुखजिंदर रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा भी चाहते थे कि किसी तरह से यह घोषणा हो जाए कि राजा वारिंग सीएम पद के दावेदार नहीं हैं.

चुनाव शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा

3 मंत्रियों के जिले में कांग्रेस को झटका

नवभारत कनेक्ट

शिमला, 17 सितंबर. करीब 26 सालों के बाद शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो गया. भाजपा की जीत कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है.

जिला शिमला से राज्य सरकार में तीन मंत्री होने के बावजूद सत्तारूढ़ कांग्रेस सीट नहीं बचा पाई. शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र से आने वाले भाजपा समर्थित प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह सिसोदिया अध्यक्ष बने.

वहीं, जुब्बल कोटखाई के टिककर वॉर्ड से निर्दलीय सदस्य भरत सिंह कलांटा को उपाध्यक्ष चुना गया. भाजपा की जीत के बाद उपायुक्त कार्यालय शिमला में भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया. इस मौके पर भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन और सिकंदर कुमार के साथ विधायक बलबीर वर्मा भी

मौजूद रहे.

इस मौके पर भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि लंबे इंजतार के बाद चुनाव हुआ और भाजपा को जीत हासिल हुई. उन्होंने कहा कि सरकार सीधे चुनाव को हटाने का प्रयास कर रही थी. भाजपा प्रत्याशियों ने इस मामले में अदालत का रुख भी किया. इसके बाद अब जाकर चुनाव करवाया गया. हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश की 12 में से 11 जिला परिषद पर भाजपा ने कब्जा किया है, जो कांग्रेस की सत्ता से विदाई के संकेत हैं.

भाजपा समर्थित प्रत्याशी भूपेंद्र सिसोदिया को 13 वोट मिले

शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए दिलचस्प मुकाबले में भाजपा ने नजदीकी अंतर से जीत हासिल की. 25 सदस्यों वाली शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी भूपेंद्र सिसोदिया को 13 मत पड़े. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र रेटका के हिस्से में 10 मत आए, जबकि अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में 2 मत अमान्य करार दिए गए. इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा का कब्जा है. भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी भरत सिंह क्लांटा वाइस चेयरमैन बने. वाइस चेयरमैन पद के लिए भरत सिंह क्लांटा को 14 मत पड़े. जबकि, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मीनाक्षी को 10 मत पड़े

मिशन 2027 : भाजपा का सुपर प्लान

हर बूथ पर उतरेगी 60 वालंटियरों की फौज

नवभारत कनेक्ट

लखनऊ, 17 सितंबर. उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक योजना में बड़ा बदलाव किया है.

पार्टी ने प्रदेश भर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर सूक्ष्म प्रबंधन यानी माइक्रोमैनेजमेंट को बेहद मजबूत बनाने का फैसला किया है. इस विशेष रणनीति के तहत पार्टी के विभिन्न अग्रिम मोर्चे हर बूथ पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे. इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन की पकड़ को अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाना है. इस नई योजना के अंतर्गत भाजपा के पांच प्रमुख मोर्चे - युवा, किसान, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चे को जिम्मेदारी दी गई है. ये सभी मोर्चे प्रत्येक बूथ पर अनिवार्य रूप से दस-दस समर्पित कार्यकर्ताओं को वालंटियर के रूप में तैनात करेंगे.

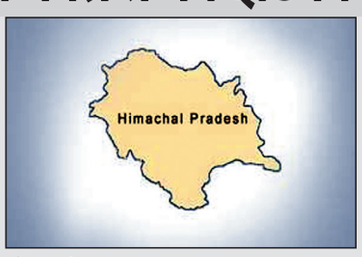

इस तरह एक ही मतदान केंद्र पर कुल मिलाकर पचास से साठ नए वालंटियर कार्य करेंगे.

यह व्यवस्था पार्टी के मूल बूथ अध्यक्ष और उनकी नियमित टीम के अतिरिक्त काम करेगी.

सामाजिक गणित और सर्वे रिपोर्ट की योजना

वालंटियरों के चयन में संबंधित मतदान क्षेत्र के सामाजिक और जातीय संतुलन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा. जिस इलाके में जिन जातियों की आबादी अधिक होगी, उसी वर्ग के स्थानीय कार्यकर्ताओं को वालंटियर बनाया जाएगा. यह टीम अपने-अपने समाज के लोगों के बीच जाकर सरकार की नीतियों का प्रचार करेगी. इसके साथ ही, चुनाव से ठीक पहले ये वालंटियर अपने क्षेत्र की विस्तृत राजनीतिक और सामाजिक सर्वे रिपोर्ट सीधे पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे.

ओबीसी-दलितों पर फोकस और नए उम्मीदवारों को अवसर

उत्तर प्रदेश के सभी 98 सांगठनिक जिलों में फैले लगभग पौने दो लाख बूथों पर इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी पूरी है. पार्टी इस बार विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग और दलित मतदाताओं को साधने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है. प्राप्त सर्वे रिपोर्टों के व्यापक विश्लेषण के बाद भाजपा आगामी चुनाव में कई मौजूदा उम्मीदवारों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे सकती है, जिससे संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो सके.